

प्रेषक,

पी०के०महान्ति,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास,

उत्तराखण्ड पौड़ी

ग्राम्य विकास अनुभाग

देहरादून: दिनांक 20 मार्च, 2007

**विषय:-** टी०डी०ई०टी० के अन्तर्गत हाईड्रम स्थापना हेतु राज्यांश को वर्ष 2006-07 में  
अयमुक्त का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक -2194/5-लेखा/टी०डी०ई०टी०/2006-07 दिनांक 25-9-2006 भारत सरकार के शासनादेश संख्या-5-3/2002 टी०ई० दिनांक 9-1-2006, के संदर्भ एवं शासनादेश संख्या -40/XI /2006/56(66)/2003 दिनांक 13 फरवरी, 2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टी०डी०ई०टी० के अन्तर्गत जनपद नैनीताल हेतु हाईड्रम की स्वीकृत यूनिट हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में राज्यांश के रूप में अवशेष धनराशि रु० 4.75 लाख(रु० चार लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अयमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय विनोदित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. उक्त धनराशि का आहरण भारत सरकार के केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने /प्राप्त धनराशि की पुनर्विध करान के पश्चात् ही स्वीकृत परिषद की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

3. उक्त धनराशि का आवंटन वर्तमान नियमों/ओडशों तथा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत /गाइडलाईन्स के अनुसार योजना के अंतर्गत किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से भारत सरकार /राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाय। धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा।

5- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का समस्त दाहित्व सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी का होगा।

6- कार्य करते समय मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पंच रूलस/डी०जी०एस० एण्ड ही अथवा टेंडर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31-3-3007 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

8- योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मध्य राज्य में लागू आरक्षण प्रतिशतता के आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं में किया जायेगा।

9- उक्त पैरा-2 से 8 तक में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात नियंत्रक /मुख्य/वरिष्ठ /सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

10. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के अनुदान संख्या -31 के लेखा शीर्षक -2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम -00--796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना -01 हाईड्रम परियोजना /टी.डी.ई.पी. हेतु राज्यांश -00-20 सहायक अनुदान /अंशदान /राज सहायता सं० रु० 4,75,000 की धनराशि सुरंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

11. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-978/वित्त अनुभाग -4/2007 दिनांक 19 मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(पी०के०महान्ति)  
सचिव।

संख्या 144 (1)/XI /06/56(66) 2003 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सम्बन्धित वरिष्ठ कौषाधिकारी/कौषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 3- अनु सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, डिपार्टमेन्ट आफ लैंड रिसोर्स भारत सरकार एन. बी.ओ. विल्डिंग, जी.विंग निर्माण भवन नई दिल्ली।
4. आयुक्त, कूमायूँ मण्डल नैनीताल।
5. संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास पौड़ी।
6. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र देहरादून।
9. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनु-4, उत्तराखण्ड शासन।
10. नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(दमयन्ती दोहरे)  
अपर सचिव